अरुणाचल में स्कूल हैं , मगर पूरे अध्यापक नहीं हैं। अस्पताल हैं, पर डाक्टर्ज सभी अस्पतालों में नहीं हैं। वहां भूमि सारे गांव के नाम पर है और उसीमें खेती-योग्य भूमि या चरागाह की भूमि या गांव-वन सामूहिक ग्राम सम्पत्ति है। हर परिवार को इस सामूहिक सम्पति में खेती योग्य भूमि ग्राम एलाट कर देता है। जब कभी सरकार ऐसी भूमि का अधिग्रहण करती है, तो उसका मुआवजा नहीं मिलता। कहा जाता है कि खेती सारे गांव के नाम पर दर्ज है। इस कारण सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत और बैंकों के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत भी किसानों को ऋण की सुविधा भी नहीं है। स्पष्ट है कि देश की विविधता को ध्यान में रखकर इन नियमों में आवश्यक परिवर्तन नहीं किया गया है।

फलस्वरूप अरुणाचल में असंतोष व्याप्त है। इसे ध्यान में रखते हुए और देश की सुरक्षा की दृष्टि से, इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए मेरी मांग है कि सरकार इन सभी प्रश्नों के संबंध में तत्काल एक केन्द्रीय टीम भेज कर समस्याओं का प्रभावी निराकरण निकालने की कृपा करें।

(viii) Need to open a big factory in Jabalpur, M.P., to solve unemployment problem in that area.

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश अत्यन्त पिछड़ा है तथा मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला, जो कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का मध्य बिंदु है, उद्योगों में एकदम पिछड़ा है। यह भी सच्चाई है कि जबलपुर में दो विश्वविद्यालय हैं, प्रदेश का उच्च न्यायालय है तथा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का प्रमुख कार्यालय भी है। वहां सुरक्षा संस्थानों की भरमार है, जैसे कि आयुध निर्माण कारखाना, आर्डनेंस फैक्टरी, लोहा घूसर कारखाना (ग्रे आयरन फ़ाउन्ड्री) तथा अन्य अनेक संस्थान। इन सुरक्षा संस्थानों में साठ हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। बीड़ी बनाने के उद्योग में भी इस जिले में तीन लाख से ऊपर श्रमिक कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र जबलपुर शहर है तथा लगभग एक लाख विद्यार्थी यहां पर अध्ययनरत रहते हैं।

जैसा कि मैंने कहा है, औद्योगिक दृष्टि से जबलपुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर अपार खनिज सम्पदा है तथा विपुल जल भी है। परन्तु उनका उचित साधनों से दोहन नहीं हो रहा है। कारण यह है कि सुरक्षा संस्थानों में लगी पूंजी के कारण यह जिला औद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील अर्थात एडवांस्ड माना जाता है।

इन सारी अधिकताओं के साथ-साथ बेरोजगारी की भी अधिकता है। पूरे विंध्य संभाग, सागर संभाग तथा जबलपुर संभाग अर्थात 17 जिलों के बेरोजगार नवयुवक जबलपुर में काम-धंधे की तलाश में आते हैं तथा इस कारण एक लाख से भी अधिक बेरोजगार अकेले जबलपुर शहर में हैं। इन समस्याओं के निराकरण हेतु मैं उद्योग मंत्री जी से निम्नलिखित निवेदन करता हूं—

(1) जबलपुर जिले के पनागर विधानसभा क्षेत्र, जो कि आदिवासी है, तथा सिहोरा तहसील को उद्योगों के हिसाब से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए।

(2) खनिज संपदा को मद्देनजर रखते हुए कोई बड़ा कारखाना इस क्षेत्र में खोला जाए।

(ix) Central assistance for solving drinking water problem in Midnapur and Kharagpur towns of West Bengal.

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore) : Acute and severe scarcity of water in the towns of Midnapur and Kharagpur in West Bengal is causing serious hardships to lakhs of inhabitants of these towns. In Midnapur, waterworks has completely collapsed and a little supply of water is being made through tankers where people are fighting for a bucket of water. In Kharagpur Railway Colony, water supply is becoming scarcer every day. In the Municipal town, water